



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

File  
3/10/47

सं० 268]  
No. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 1997/आषाढ़ 13, 1919  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 1997/ASADHA 13, 1919

वित्त मंत्रालय

(समझौता आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1997

**आय-कर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1997**

**सा. का. नि. 361(अ)**—आयकर समझौता आयोग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245च की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1987 को, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

- (i) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;
- (ii) "उपाबंध" से आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में उपवर्णित, प्ररूप सं. 34ख में उपाबंध अभिप्रेत है;
- (iii) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने से संबंधित मामले के समझौते के लिए धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आयोग को आवेदन करता है ;
- (iv) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से, —

(क) आवेदक के संबंध में, सिवाय तब जब ऐसे आवेदक से अधिनियम के अध्याय 19क के किन्हीं उपबन्धों के अधीन स्वयं हाजिर होने की अपेक्षा की जाए, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 288 के अधीन किसी आयकर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने का हकदार हो ;

(ख) आयुक्त के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे,—

- (i) आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो : या
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत रूप में, आयुक्त के समक्ष किसी कार्यवाही में आयुक्त की ओर से, यथास्थिति, हाजिर होने, अभिवचन करने या कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो :
- (iii) "आयोग" से धारा 245ख की उपधारा (1) के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, कोई भी न्यायपीठ है जो आयोग की शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन करती है :
- (iv) "आयोग के अधिकारी" से सचिव, आयकर निदेशक (अन्वेषण), आयकर अपर निदेशक (अन्वेषण) और आयकर उप-निदेशक (अन्वेषण) अभिप्रेत है :
- (v) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी भी हैं :
- (vi) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है :
- (vii) "समझौता आवेदन" से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने से संबंधित मामले के समझौते के लिए धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आयोग को किया गया हो :
- (viii) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो इनके अधिनियम में हैं।

3. **आयोग की भाषा**—(1) आयोग के समक्ष सभी अभिवचन आवेदक के विकल्प पर हिन्दी या अंग्रेजी में किये जाएंगे।

(2) आयोग के सभी आदेश और अन्य कार्यवाहियां, आयोग के विकल्प पर हिन्दी या अंग्रेजी में की जा सकेंगी।

4. **सूचनाओं आदि का हस्ताक्षरित किया जाना** : (1) आयोग द्वारा जारी की जाने वाली कोई अध्यक्षता, निर्देश, पत्र, प्राधिकार, आदेश या लिखित सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या आयोग के किसी अन्य सदस्य द्वारा या सचिव द्वारा (या आयोग के किसी अधिकारी द्वारा) हस्ताक्षरित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) की कोई बात ऐसी किसी अध्यक्षता या निर्देश को लागू नहीं होगी जिसे आयोग, सुनवाई के दौरान किसी आवेदक या आयुक्त या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से जारी करें।

5. **समझौता आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया**—(1) समझौता आवेदन, आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 11 में उपवर्णित प्रारूप में, 34ख में, आवेदक द्वारा स्वयं या उसके अधिकारी द्वारा आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सचिव को या ऐसी न्यायपीठ के सचिव को जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका मामला आता है या या ऐसे किसी अधिकारी को जिसे सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत किया जाएगा अथवा सचिव या ऐसे अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन डाक द्वारा भेजे गये किसी समझौता आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सचिव को या सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उस तारीख को प्रस्तुत किया गया है जिस तारीख को यह आयोग के कार्यालय में प्राप्त होता है।

6. **धारा 245घ (1) के अधीन आयुक्त की रिपोर्ट आदि**—समझौता आवेदन प्राप्त होने पर उक्त आवेदन की एक प्रति (उपाबंध से भिन्न) आयोग द्वारा आयुक्त को इस निर्देश के साथ अत्रिपित की जाएगी कि वह धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन अपनी रिपोर्ट उसके द्वारा आवेदन की उक्त प्रति प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

7. **पेपर बुक आदि की तैयारी** :—(1) यदि, यथास्थिति, आवेदक या आयुक्त किसी दस्तावेज या विवरणी या अन्य पेपरों को निर्दिष्ट करना चाहता है या उन पर निर्भर करना चाहता है तो उसे अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन सुनवाई की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले पेपर बुक की छह प्रतियां जिनमें ऐसे पृष्ठ सम्यक् रूप से अनुक्रमणित हों और पृष्ठ संख्यांक डाले गए हों, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु, समुचित मामले में आयोग विम्वर के लिए माफी दे सकेगा और पेपरबुक स्वीकार कर सकेगा।

(2) यदि आवेदक अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन सुनवाई के दौरान किन्हीं दस्तावेजों, विवरणियों या अन्य पेपरों को निर्दिष्ट करना चाहता है या उन पर निर्भर करना चाहता है तो वह धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी बड़ाई गई अवधि के भीतर जिसे आयोग ने अनुज्ञप्त किया हो, छह प्रतियां जिसमें ऐसे पृष्ठ सम्यक् रूप से क्रमोणित किए गए हों और पृष्ठ संख्यांक डाले गये हों, प्रस्तुत करें।

(3) यदि आयुक्त अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन सुनवाई के दौरान किन्हीं दस्तावेजों या विवरणियों या अन्य पेपरों को निर्दिष्ट करना चाहता है या उन पर निर्भर करना चाहता है तो वह नियम 9 में निर्दिष्ट अपनी रिपोर्ट के साथ उनकी छह प्रतियां जिनमें ऐसे पृष्ठ अनुक्रमणित किए गए हों और पृष्ठ संख्यांक डाले गये हों, प्रस्तुत करें।

(4) आयोग, स्वरूप, स्थिति, आवेदक या आयुक्त के खर्च पर पेपर बुक की छह प्रतियाँ तैयार कराने का निर्देश दे सकेगा जिनमें ऐसे विवरण दस्तावेज और पेपर आदि हों, जिन्हें वह समझौता आवेदन या उससे उद्भूत प्रश्नों के समुचित निपटारे के लिए आवश्यक समझता है।

(5) उपनियम (1), (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट पेपर भुपाद्य रूप में लिखे या दोहरे स्पेस में टाइप किए गए या मुद्रित होने चाहिए। यदि दस्तावेजों की जैरेक्स प्रति फाइल की गई है तो उसे सुपाद्य होना चाहिए। प्रत्येक पेपर, उसे फाइल करने वाले पक्षकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यप्रतिनिधि के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए और वह ऐसी रीति में अनुक्रमणित किया गया हो जो, पृष्ठ संख्यांक तथा उस प्राधिकारी का जिसके समक्ष उसे फाइल किया गया था सहित, दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण देता हो।

**8. शपथपत्र फाइल किया जाना—**जहां समझौता आवेदन में (इसके अन्तर्गत उपाबंध और ऐसे उपाबंध से संलग्न विवरणी या अन्य दस्तावेज भी हैं) अधिकृत कोई तथ्य ऐसा है जो मामले से संबंधित अभिलेख से साबित नहीं किया जा सकता, अथवा उसके प्रतिकूल है तो इसे स्पष्ट रूप से और संक्षेप में कथित किया जाएगा और सम्यक् रूप से शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।

**9. आयुक्त की अतिरिक्त रिपोर्ट—**जब आयोग द्वारा धारा 245 घ की उपधारा (1) के अधीन समझौता आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुज्ञा देते हुए आदेश पारित किया जाता है वह उक्त आवेदन के उपाबंध ऐसे उपाबंध से संलग्न प्रत्येक विवरणी और अन्य दस्तावेजों के साथ आयुक्त को, उक्त आदेश की एक प्रति के साथ और इस निर्देश के साथ अर्पित की जाएगी कि आयुक्त ऐसी अतिरिक्त जांच या अन्वेषण, जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् धारा 245घ की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 245ग की उपधारा (3) के अधीन आवेदन से संबंधित विषयों में या मामले से संबंधित किसी अन्य बात के लिए उक्त उपाबंधों (इसमें इसके साथ संलग्न विवरणी और अन्य दस्तावेज सम्मिलित हैं) की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करेगा। यदि आयुक्त पैंतालीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर या उसके पहले अपनी रिपोर्ट भेजने में असफल रहता है तो आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

**10. आवेदन की सुनवाई की तारीख और स्थान का अधिसूचित किया जाना—**नियम 9 में निर्दिष्ट आयुक्त की अतिरिक्त रिपोर्ट, यदि कोई है, की प्राप्ति पर आयोग आवेदक को और आयुक्त को आवेदन की सुनवाई की तारीख और स्थान अधिसूचित करेगा।

**11. न्यायपीठ की बैठक —**न्यायपीठ अपने मुख्यालय में अपनी बैठकें करेगा। पीठासीन अधिकारी के विवेक पर न्यायपीठ आयोग द्वारा निर्दिष्ट अपनी अधिकारिता वाले किसी भी स्थान पर कर सकेगी।

**12. न्यायपीठ की शक्तियाँ —**न्यायपीठ ऐसे समझौता आवेदनों या उनसे उत्पन्न होने वाले विषयों का निपटारा करेगी जिन्हें अध्यक्ष साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

**13. विशेष न्यायपीठ का गठन —**(1) अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए विशेष न्यायपीठ का गठन कर सकेगा जिसमें आयोग की सभी न्यायपीठों से लिए गए कम से कम पांच सदस्य होंगे।

(2) विशेष न्यायपीठ में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पीठासीन होगा।

(3) यदि विशेष न्यायपीठ के सदस्य राय में बराबर बंटे हुए हैं तो वे उस विषय बिन्दु या विषय बिन्दुओं का उल्लेख करेंगे जिन पर वे भिन्न राय रखते हैं और उसे उन्हें अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेंगे, जो उस विषय बिन्दु या विषय बिन्दुओं के संबंध में समझौता आयोग के अन्य सदस्यों में से एक या अधिक द्वारा सुनवाई के लिए मामले को निर्दिष्ट करेगा और ऐसा विषय बिन्दु, विषय बिन्दुओं का विनिश्चय समझौता आयोग के उन सदस्यों की, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

(4) इस नियम के पूर्वोक्त उपाबन्ध में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि विशेष न्यायपीठ का गठन करने वाला एक या अधिक व्यक्ति (चाहे ऐसा व्यक्ति विशेष न्यायपीठ का पीठासीन अधिकारी है या कोई अन्य सदस्य) बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से विशेष न्यायपीठ से कृत्य करने में असमर्थ है या विशेष न्यायपीठ के पीठासीन अधिकारी के पद में या उसके एक या अन्य सदस्यों के पद में रिक्त हो गई है तो शेष सदस्य, यदि वे तीन से अधिक हैं, विशेष न्यायपीठ के रूप में कृत्य कर सकेगा और शेष सदस्यों में से ज्येष्ठतम सदस्य विशेष न्यायपीठ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।

**14. प्राधिकार का फाइल किया जाना—**किसी आवेदन की सुनवाई के संबंध में आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाला कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई आरम्भ होने से पहले उसे आवेदक के लिए उपस्थित होने को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज फाइल करेगा और यदि वह आवेदक का संबंधी है तो दस्तावेज में आवेदन के साथ उसके संबंध की प्रकृति का कथन करेगा और यदि वह आवेदक द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है तो उसमें उसकी उस हैसियत का, जिसमें वह उस समय नियोजित है, कथन करेगा।

**15. अतिरिक्त तथ्यों का सत्यापन—**जहां आयोग के समक्ष कार्यवाही के दौरान ऐसे तथ्यों पर निर्भर होने की संख्या की गई है जो समझौता आवेदन (इसमें उपाबंध और ऐसे उपाबंध से संलग्न विवरणी तथा अन्य दस्तावेज भी सम्मिलित हैं) में अन्तर्निहित नहीं है तो उन्हें लिखित रूप में आयोग को पेश किया जाएगा और उसी रीति में उनका सत्यापन किया जाएगा जैसा समझौता आवेदन में उपबन्धित है।

**16. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुली न होना—** आयोग के समक्ष की कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होंगी और कोई व्यक्ति (आवेदक, उसका कर्मचारी, आयोग या आयकर विभाग के संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधियों से भिन्न) आयोग की अनुज्ञा के बिना ऐसी कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं रहेगा।

**17. विशेष न्यायपीठ के आदेशों का प्रकाशन —** अध्यक्ष, अपने विवेक पर आदेशों या ऐसे अंशों के, जिनमें विशेष न्यायपीठ के विनिर्णय अन्तर्निष्ठ हों, प्रकाशन का निर्देश, ऐसे उपान्तरो सहित, जो वह उचित समझे दे सकेगा।

**18 सुनवाई का स्थगित किया जाना—** आयोग ऐसे निबन्धनों के साथ, जिन्हें वह उचित समझता है और कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, आवेदन की या उससे उद्भूत किसी मामलों की सुनवाई, स्थगित कर सकेगा।

**19. 1 अक्टूबर, 1984 से पूर्व किए गए समझौता आवेदन की बाबत विशेष उपबंध—**(1) जहां 1 अक्टूबर, 1984 से पूर्व किए गए किसी समझौता आवेदन की बाबत आयोग द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करने का कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन पारित किया जाता है, वहां आयोग द्वारा आवेदक से निम्नलिखित की पांच प्रतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

(क) उन विषयों की बाबत जिनका समझौता किया जाना है (जिसके अन्तर्गत वह रीति भी है जिसमें आवेदक द्वारा प्रकट की गई या प्रकट किए जाने के लिए प्रस्थापित कोई आय हासिल की गई है), के तथ्यों का एक पूरा और सत्य विवरण और जहां समझौता में आय का अवधारण सम्मिलित है वहां उसके साथ उपाबंधों सहित निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(i) उम निर्धारण वर्ष या उन निर्धारण वर्षों के लिए जिसमें समझौता आवेदन संबंधित है, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में आवेदक की कुल आय की संगणना,

(ii) यथास्थिति, विनिर्माण खाता या व्यापार खाता अथवा दोनों की प्रतियां, यथास्थिति लाभ और हानि लेखा या आय और व्यय लेखा तथा तुलनपत्र, और

(iii) निम्नलिखित की दशा में, अर्थात् —

(क) साम्प्रतिक कारोबार या वृत्ति की दशा में स्वामी के व्यक्तिगत खाते की एक प्रति,

(ख) फर्म या व्यक्ति संगम या व्यष्टियों के निकाय की दशा में, यथास्थिति, उसके भागीदारों या सदस्यों के व्यक्तिगत खातों की प्रतियां, और

(ग) फर्म के भागीदारों या व्यक्ति संगम या व्यष्टियों की निकाय के किसी सदस्य की दशा में, यथास्थिति, फर्म या व्यक्ति संगम या व्यष्टियों के निकाय में ऐसे भागीदार या सदस्य के व्यक्तिगत खातों की प्रतियां,

(ख) आवेदक द्वारा वांछित समझौते के निबन्धन।

(2) तथ्यों का विवरण उसके उपाबंधों और समझौतों के निबन्धनों में से प्रत्येक आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होंगे तथा तथ्यों का विवरण निम्नलिखित रीति से सत्यापित होगा, अर्थात् :—

मैं ————— सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ————— सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करते हूँ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम)

हैं कि तथ्यों के विवरण तथा संलग्न उपाबंध में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही तथा पूर्ण हैं और उनमें दिखाई गई विशिष्टियां सत्यतापूर्वक वर्णित हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं यह विवरण ————— (पदनाम) की हैसियत में दे रहा हूँ/रही हूँ और मैं तथ्यों का यह विवरण देने के लिए तथा उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान —————

हस्ताक्षर —————

तारीख —————

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन दाखिल किए गए तथ्यों के विवरण में अभिकथित कोई तथ्य ऐसा है जो मामले से संबंधित अभिलेख से स्थापित नहीं किया जा सकता अथवा उसके प्रतिकूल है, तो यह स्पष्टरूप से तथा संक्षेप में कथित किया जाएगा और सम्यक् रूप से शपथित शपथपत्र से समर्थित होगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन तथ्यों का विवरण और समझौते के निबन्धनों की प्राप्ति पर आयोग उसकी एक प्रति आयुक्त को उस पर उसकी और रिपोर्ट मांगते हुए भेजेगा।

[ फा. सं. 1/49/तकनीकी/97/एस सी/1239 ]

बरजिन्दर सिंह, सचिव, आयकर समझौता आयोग

## MINISTRY OF FINANCE

(Settlement Commission)

### NOTIFICATION

New Delhi, 4th July, 1997

### THE INCOME TAX SETTLEMENT COMMISSION (PROCEDURE) RULES, 1997

**G.S.R. 361(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 245F of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the Income-tax Settlement Commission (Procedure) Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Income-tax Settlement Commission hereby makes the following rules, namely :—

**Short title and commencement :—**(1) These rules may be called the Income-tax Settlement Commission (Procedure) Rules, 1997.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Definitions :—**In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (i) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
- (ii) "annexure" means the annexure to the application in Form No. 34B, set out in Appendix II to Income-tax rules, 1962.
- (iii) "applicant" means a person who makes an application to the Commission under sub-section (1) of section 245C to have a case relating to him settled;
- (iv) "authorised representative" means, —
  - (a) in relation to an applicant, except where such applicant is required under any of the provisions of Chapter XIX-A of the Act to attend in person, a person who would be entitled to represent him before any income-tax authority or the Appellate Tribunal under section 288,
  - (b) in relation to a Commissioner, a person, —
    - (i) authorised in writing by the Commissioner or the Chief Commissioner; or
    - (ii) duly appointed by the Central Government as authorised representative or duly authorised by the Central Board of Direct Taxes to appear, plead and act for the Commissioner in any proceeding before the Commission;
- (v) "Commission" means the Income-tax Settlement Commission constituted under sub-section (1) of section 245B and includes, where the context so requires, any Bench exercising or discharging the powers or functions of the Commission.
- (vi) "Officer of the Commission" means Secretary, Director of Income tax (Investigation), Additional Director of Income-tax (Investigation) and Deputy Director of Income-tax (Investigation).
- (vii) "Secretary" means Secretary of the Commission and includes an Administrative Officer
- (viii) "Section" means a section of the Act;
- (ix) "Settlement application" means an application made by a person to the Commission under subsection (1) of section 245C to have a case relating to him settled;
- (x) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act :

**3. Language of the Commission :—**(1) All pleadings before the Commission may, at the option of the applicant, be in Hindi or in English.

(2) All orders and other proceedings of the Commission may, at the option of the Commission, be in Hindi or in English.

**4. Signing of notices etc. :—**(1) Any requisition, direction, letter, authorisation, order or written notice to be issued by the Commission shall be signed by the Chairman or a Vice-Chairman or any other Member of the Commission or by Secretary (or by any other officer of the Commission);

(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to any requisition or direction which the Commission may, in the course of the hearing, issue to an applicant or a Commissioner or an authorised representative personally

**5. Procedure for filing settlement application :—**(1) A settlement application shall be presented in Form No. 34B, set out in Appendix II to Income-tax Rules, 1962, by the applicant in person or by his agent, to the Secretary at the headquarters of the Commission at New Delhi or of the Bench within whose jurisdiction his case falls or to any officer authorised in this behalf by the Secretary, or shall be sent by registered post addressed to the Secretary, or to such officer.

(2) A settlement application sent by post under sub-rule (1) shall be deemed to have been presented to the Secretary or the officer authorised by the Secretary on the day on which it is received in the office of the Commission.

**6. Commissioner's report etc. under section 245D(1) :—**On receipt of a settlement application, a copy of the said application (excluding the Annexure) shall be forwarded by the Commission to the Commissioner with the direction to furnish his report under sub-section (1) of section 245D within 45 days of the receipt of the said copy of the application by him.

**7. Preparation of paper books etc. :—**(1) If the applicant or the Commissioner, as the case may be, proposes to refer or rely upon any documents or statements or other papers, he may submit six copies of a paper book containing such papers duly indexed and paged at least two weeks before the date of hearing under sub-section (1) of section 245D of the Act,

Provided, however, the Commission may in an appropriate case condone the delay and admit the paper book.

2. If the applicant proposes to refer or rely upon any documents or statements or other papers, during the course of hearing under sub-section (4) of section 245D, of the Act, he may submit six copies of a paper book containing such papers duly indexed and paged, within thirty days or within such extended period as may be allowed by the Commission, of the receipt of an order under sub-section (1) of section 245D.

(3) If the Commissioner proposes to refer or rely upon any documents or statements or other papers during the course of hearing under sub-section (4) of section 245D of the Act, he may submit six copies of a paper book containing such papers duly indexed and paged along with his report referred in rule 9.

(4) The Commission may, suo moto, direct the preparation of six copies of paper book by and at the cost of the applicant or the Commissioner, as the case may be, containing copies of such statements, documents and papers etc. as it may consider necessary for the proper disposal of the settlement application or matters arising therefrom.

(5) The papers referred to in sub-rules (1), (2), (3) and (4) must be legibly written or type-written in double space or printed. If xerox copy of the documents is filed, then the same should be legible. Each paper should be certified as a true copy by the party filing the same, or his authorised representative and indexed in such a manner as to give brief description of the documents, with page numbers and the authority before whom it was filed

**8. Filing of affidavit :—**Where a fact, which is not borne out by or is contrary to the record relating to the case, is alleged in the settlement application (including the annexure and the statement or other documents accompanying such annexure), it shall be stated clearly and concisely and supported by a duly sworn affidavit.

**9. Commissioner's further report :—**Where an order is passed by the Commission under sub-section (1) of section 245D allowing the settlement application to be proceeded with, a copy of the annexure to the said application, altogether with a copy each of the statements and other documents accompanying such annexure, shall be forwarded to the Commissioner along with a copy of the said order with the direction that the Commissioner shall furnish a further report on the matters covered by the application and any other matter relating to the case under sub-section (3) of section 245D read with sub-section (2) of section 245F after making such further enquiry or investigation as necessary within 45 days of the receipt of the said annexures (including the statements and other documents accompanying them) or within such further period as the Commission may specify. If the Commissioner fails to furnish his report on or before the expiry of the specified period of 45 days or such extended period, the Commission may pass the appropriate order without such report.



**10. Date and place for hearing of application to be notified :—**On receipt of the Commissioner's further report, if any, referred to in Rule 9, the Commission shall notify to the applicant and the Commissioner the date and place of hearing of the application.

**11. Sitting of Bench :—**A Bench shall hold its sittings at its headquarters. The Bench may, however, at the discretion of the Presiding Officer, hold its sittings at any place in its jurisdiction notified by the Commission.

**12. Powers of a Bench :—**A Bench shall dispose of such settlement applications or matters arising therefrom as the Chairman may by general or special order direct.

**13. Constitution of Special Bench :—**(1) The Chairman may, for the disposal of any particular case, constitute a Special Bench consisting of at least five Members drawn from all the Benches of the Commission.

(2). The Special Bench shall be presided over by the Chairman or a Vice-Chairman.

(3). If the Members of Special Bench are equally divided, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the Chairman who shall refer the case for hearing on such point or points by one or more of other Members of the Settlement Commission and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the Members of the Settlement Commission who have heard the case.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this rule, if one or more persons constituting the Special Bench (whether such person is the Presiding Officer or any other Member of the Special Bench) are unable to function in the Special Bench owing to illness or any other cause or in the event of occurrence of a vacancy either in the office of the Presiding Officer or in the office of one or other Members of the Special Bench, the remaining Members, if more than three, may function as the Special Bench, and the senior most of the remaining Members shall act as the Presiding Officer of the Special Bench.

**14. Filing of authorisation:—**An authorised representative appearing for the applicant at the hearing of an application shall file before the commencement of the hearing a document authorising him to appear for the applicant and if he is a relative of the applicant, the document shall state the nature of his relationship with the applicant, or if he is a person regularly employed by the applicant, the capacity in which he is at the time employed.

**15. Verification of additional facts:—**Where in the course of any proceedings before the Commission any facts not contained in the settlement application (including the annexure and the statements and other documents accompanying such annexure) are sought to be relied upon, they shall be submitted to the Commission in writing and shall be verified in the same manner as provided for in the settlement application.

**16. Proceedings not open to the public:—**The proceedings before the Commission shall not be open to the public and no person (other than the applicant, his employee, the concerned officers of the Commission or the Income-tax Department or the authorised representatives) shall, without the permission of the Commission, remain present during such proceedings.

**17. Publication of orders of the Special Bench:—**The Chairman may, at his discretion, direct the publication of orders or portions containing the rulings of the Special Bench with such modifications as to names and other particulars, therein as he may deem fit.

**18. Adjournment of hearings:—**The Commission may, on such terms as it thinks fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the application or any matters arising therefrom.

**19. Special provisions in respect of settlement applications made before 1st day of October, 1984:—**(1) Where, in respect of a settlement application made before the 1st day of October 1984, an order is passed by the Commission under sub-section (1) of section 245D of the Act allowing the application to be proceeded with, a notice shall be issued by the Commission to the applicant requiring him to furnish in quintuplicate

(a) a full and true statement of facts regarding the matters to be settled (including the manner in which any income disclosed or proposed to be disclosed by the applicant has been derived), and where the settlement involves determination of income, accompanied with annexures containing :—

(i) Computation of total income of the applicant for the assessment year or years to which the settlement application relates, in accordance with the provisions of the Act;

(ii) Copies of manufacturing account or trading account or both, as the case may be, profit and loss account or income and expenditure account or any other similar account, as the case may be, and balance sheet; and

(iii) in the case of:—

- (a) a proprietary business or profession, copy of the personal account of the proprietor;
- (b) a firm or association of persons or body of individuals, copies of the personal accounts of the partners or members thereof, as the case may be; and
- (c) a partner of a firm or a member of an association of persons or body of individuals, copies of the personal account of such partner or member in the firm or association of persons or body of individuals, as the case may be;

(b) the terms of settlement sought for by the applicant.

(2) The statement of facts, the annexures thereto and the terms of settlement shall each be signed separately by the applicant and the statement of facts shall be verified in the following manner, namely:—

"I.....son/daughter/wife of

(Name in full and in block letters)

..... solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this statement of facts and the annexures accompanying it is correct and complete and other particulars shown therein are truly stated. I further declare that I am making this statement in my capacity as.....and

(designation)

that I am competent to make this statement of facts and to verify it.

Place .....

Date .....

Signature

(3) Where a fact which cannot be borne out by or is contrary to the record relating to the case is alleged in the statement of facts furnished under sub-rule (1), it shall be stated clearly and concisely and supported by a duly sworn affidavit.

(4) On receipt of the statement of facts and the terms of settlement under sub-rule (1), the Commission shall forward a copy thereof to the Commissioner calling for his further report.

[F. No. 1/49/Tech/97/SC/1239]

BERJINDER SINGH, Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1997

**सा.का.नि. 362 (अ).**— धनकर समझौता आयोग, धन-कर समझौता आयोग धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 22 च की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धन-कर समझौता आयोग प्रक्रिया नियम, 1987 को, सिखाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1997 है ।  
(2) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1997 का लागू होना— आयकर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के उपबन्ध, यथाशक्य, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 22ख की उपधारा (1) के अधीन गठित धन-कर समझौता आयोग की प्रक्रिया को लागू होंगे, अर्थात् :—



(क) नियम 2 का उपान्तरण—उक्त नियमों के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

**2. परिभाषाएं:—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (i) "अधिनियम" से धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) अभिप्रेत है,
- (ii) आवेदक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 22ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन अपने से संबंधित मामले के निपटारे के लिए आयोग को आवेदन करता है ।
- (iii) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से—
  - (क) "आवेदक" के संबंध में, मियाय जब तक ऐसे आवेदक से अधिनियम के अध्याय 5क के किसी उपबन्धों के अधीन स्वयं हाजिर होने की अपेक्षा की जाए, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 44 के अधीन किसी धन-कर प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने का उत्तरदाय हो ;
  - (ख) आयुक्त के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे —
    - (i) आयुक्त या मुख्या आयुक्त द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो, या
    - (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में आयुक्त की ओर से हाजिर होने, अभिवचन करने या कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो ;
  - (iii) "आयोग" से अधिनियम की धारा 22ख की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित धन-कर समझौता आयोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, कोई भी न्यायपीठ है जो आयोग की शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन करती है ;
  - (iv) "आयोग के अधिकारी" से आयोग का सचिव, धनकर निदेशक ( अन्वेषण ), धनकर अपर निदेशक ( अन्वेषण ) और धनकर उप-निदेशक ( अन्वेषण ) अभिप्रेत है ;
  - (v) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी भी हैं;
  - (vi) "धारा" से अधिनियम धारा अभिप्रेत है
  - (vii) "समझौता आवेदन" से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने से संबंधित मामले के समझौतों के लिए धारा 22ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन आयोग को किया गया हो ;
  - (viii) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।
- (ख) नियम 5 का उपान्तरण—उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) में " 34 ख " अक्षरों और अंक के स्थान पर " ग क " अक्षर और अंक रखे जाएंगे :
- (ग) नियम 6 का उपान्तरण—उक्त नियमों के नियम 6 में, " धारा 245घ की उपधारा ( 1 ) " शब्दों कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " धारा 22घ की उपधारा ( 1 ) " शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे :
- (घ) नियम 7 का उपान्तरण—उक्त नियमों के नियम 7 में, —
  - (i) दोनों स्थानों पर आने वाले " धारा 245घ की उपधारा ( 1 ) " शब्दों " कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " धारा 22घ की उपधारा ( 1 ) " शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
  - (ii) दोनों स्थानों पर आने वाले " धारा 245घ की उपधारा ( 4 ) " " शब्दों ", कोष्ठक, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " धारा 22 घ की उपधारा ( 4 ) " शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ङ) **नियम 9 का उपान्तरण—** उक्त नियमों के नियम 9 में, " धारा 245घ की उपधारा ( 1 ) " शब्दों, कोष्ठक, अंकों और अक्षर के स्थान पर " धारा 22घ की उपधारा ( 1 ) " शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे :
- (च) **नियम 19 का उपान्तरण—** उक्त नियमों के नियम 19 में, उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“जहां 1 अक्टूबर, 1984 के पूर्व किए गए समझौता आवेदन के संबंध में आयोग द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करने का कोई आदेश धारा 22 घ की उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया है वहां आयोग द्वारा आवेदक को, पांच प्रतियों में, निम्नलिखित भेजने की एक सूचना दी जाएगी :

(क) उन विषयों की बाबत जिनका समझौता किया जाना है (जिसके अन्तर्गत वह रीति भी है जिससे आवेदक द्वारा प्रकट किया गया या प्रकट किए जाने के लिए प्रस्थापित कोई धन अर्जित किया गया है) तथ्यों का एक पूर्ण और सत्य विवरण और जहां समझौते में शुद्ध धन का अवधारण अन्तर्निहित होंगे —

(1) उस निर्धारण, वर्ष या वर्षों या उन निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जिनसे समझौता आवेदन संबंधित है, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदक के शुद्ध धन की संगणना ; और

(2) मूल्यांकन तारीख को, भारत में और बाहर अवस्थित आस्तियों (जंगम और स्थावर) और ऋणों का ब्यौरेवार विवरण ;

(ख) आवेदक द्वारा वांछित समझौते के निबन्धन ।

[फा. सं. 1/97/तकनीकी/97/एस सी/1239]

हरजिन्दर सिंह, सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi 4th July, 1997

**G.S.R. 362 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 22F of the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957) and in supersession of the Wealth-tax Settlement Commission (Procedure) Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Wealth-tax Settlement Commission hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement :** (1) These rules may be called the Wealth-tax Settlement Commission (Procedure) Rules, 1997

2. These shall come into force on the date of their publication in the Wealth-tax official gazette.

**2. Application of Income-tax Settlement Commission (Procedure) Rules 1997 :—** The provisions of the Income-tax Settlement Commission (Procedure) Rules, 1997 (here-in-after referred to as the said rules) shall apply, so far as may be, to the procedure of the Wealth-tax Settlement Commission constituted under sub-section (1) of section 22B of the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957) subject to the following modifications, namely :—

(a) modification of rule 2—For rule 2 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

(3) **Definitions :—**In these rules, unless the context otherwise requires :—

(i) “Act” means the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(ii) “applicant” means a person who makes an application to the Commission under sub-section (1) of section 22C to have a case relating to him settled ;

(iii) “authorised representative” means—

(a) in relation to an applicant, except where such applicant is required under any of the provisions of Chapter VA of the Act to attend in person, a person who would be entitled to represent him before any wealth-tax authority or the Appellate Tribunal under section 44 of the Act.

(b) in relation to a Commission, a person;

(i) authorised in writing by Commissioner or the Chief commissioner; or

(ii) duly appointed by the Central govt. as authorised representative or duly authorised by the Central Board of Direct Taxes to appear, plead and act for the Commissioner in any proceeding before the commission.

(iv) “Commission” means the Wealth-tax Settlement Commission constituted under sub-section (1) of section 22B of the Act and includes, where the context so requires, any Bench exercising or discharging the powers or functions of the Commission;

- (v) "Officers of the Commission" means Secretary of the Commission, Director of Wealth-tax (Investigation), Additional Director of Wealth-tax (Investigation), and a Deputy Director of Wealth-tax (Investigation).
- (vi) "Secretary" means a Secretary of the Commission and includes an Administrative Officer.
- (vii) "Section" means a section of the Act.
- (viii) "settlement application" means an application made by a person to the Commission under sub-section (1) of section 22C to have a case relating to him settled;
- (ix) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act;
- (b) **Modification of rule 5 :** In sub-rule (1) of rule 5 of the said rules, for the letter and figures "34B" the letters "DA" shall be substituted :
- (c) **Modification of rule 6 :**—in rule 6 of the said rules, for the words, bracket, figures and letter "sub-section (1) of section 245D" the words, bracket, figures and letter "sub-section (1) of section 22D" shall be substituted.
- (d) **Modification of rule 7 :**—In rule 7 of the said rules,—
  - (i) for the words, bracket, figures and letter "sub-section (1) of section 245D", occurring at both the places, the words, bracket, figures and letter "sub-section (1) of section 22D" shall be substituted.
  - (ii) for the words, bracket, figures and letter "sub-section (4) of section 245D" occurring at both the places, the words, bracket, figures and letter "sub-section (4) of section 22D" shall be substituted.
- (e) **Modification of rule 9:**—In rule 9 of the said rules, for the words, bracket, figures and letter "sub-section (1) of section 245D", the words, bracket, figures and letter sub-section (1) of section 22D" shall be substituted.
- (f) **Modification of rule 19:**—In rule 19 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely —
 

Where, in respect of a settlement application made before the 1st day of October, 1984, an order is passed by the Commission under sub-section (1) of section 22D allowing the application to be proceeded with, a notice shall be issued by the Commission to the applicant requiring him to furnish in quintuplicate:—

  - (a) a full and true statement of facts regarding the matters to be settled ( including the manner in which any wealth disclosed or proposed to be disclosed by the applicant has been acquired); and where the settlement involves determination of net wealth, accompanied with annexures containing—
    - (i) computation of the net wealth of the applicant for the assessment year or years to which the settlement application relates in accordance with the provisions of the Act, and
    - (ii) a detailed statement of assets (movable and immovable) and debts, located in India and outside, as on the valuation date;
  - (b) the terms of settlement sought for by the applicant.

[F.No. 1/97/Tech/97/SC/1239]

BERJINDER SINGH, Secy.

